और भी कई काम हैं हमें

हायर एजुकेशन महकमा

विभागीय वेबसाइट पब्लिक कनेक्ट एंड अकाउंटेबिलिटी का ही हिस्सा है। लेकिन हायर एजुकेशन विभाग अपनी वेबसाइट बनाने को लेकर बिल्कुल उदासीन है।

सिटी रिपोर्टर. रायपुर

उच्च शिक्षा विभाग अपनी वेबसाइट बनाने को लेकर बिल्कुल ही गंभीर नहीं दिख रहा है। अब जब अधिकारियों से इस संबंध में बात की जाती है, तो वह विभाग में और भी काम हैं कहकर इस बात पर कान नहीं धर रहे हैं। इससे लगता नहीं वेबसाइट का काम इस साल यानी 2012 में ही पूरा हो सकेगा।

कहां तो उच्च शिक्षा की वेबसाइट बनाने के लिए एक सप्ताह का वक्त मुकर्रर था। और यहां पांच महीनों के बाद भी वेबसाइट के कोई अते पते नहीं हैं। जुलाई में राजभवन में हुई विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक में उच्च शिक्षा की वेबसाइट को एक सप्ताह के अंदर-अंदर बनाने की बात कही गई थी।

इस संबंध में कुलाधिपति ने भी निर्देश दिए थे। लेकिन तमाम हील औ हुज्जत के बाद भी आज तलक वेबसाइट का काम विभाग ने न तो प्राथमिकता में ही लिया है और न अभी ही इसे जारी करने को लेकर तारीख तय कर रहा है।

नव तकनीक के इस युग में ऐसा कोई सरकारी महकमा नहीं होना चाहिए, जिसकी इंटरनेट प्रेजेंस न हो। यूं कहें कि वेब प्रेजेंस को यह महकमा तवज्जो ही नहीं देना चाहता। फिर चाहे इस संबंध में एक सप्ताह में वेबसाइट जारी करने के निर्देश जारी हुए हों, या फिर एक महीने में। डिपार्टमेंट यूं ही चलेगा।

और भी कई काम

कुछ यही जवाब उच्च शिक्षा के अधिकारी भी दे रहे हैं। हायर एजुकेशन की वेबसाइट का काम कब तक पूरा होगा, यह पूछने पर उनका कहना है कि अभी काम चल रहा है। उच्चा शिक्षा विभाग में और भी कई काम हैं, कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर ही किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि निर्देश देने के बावजूद भी उच्च शिक्षा के अधिकारी वेबसाइट के काम को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से हायर एजुकेशन की स्थिति जानने के लिए हो रहे सर्वे की पहली रिपोर्ट जारी कर दी गई है। राज्य में हायर एजुकेशन की सही स्थिति एवं जानकारी नहीं होने के कारण सर्वे में भी काफी दिक्कतें आई हैं।

डेमो वर्जन तक नहीं

पहले पहल जब उच्च शिक्षा की वेबसाइट बनाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए थे। तब अधिकारी डेमो वर्जन बनाने में अपने आपको व्यस्त बता रहे थे। अधिकारियों के अनुसार उच्च शिक्षा का डाटा बहुत अधिक है, इसलिए जुटाने में समय लग रहा है। जब सारी जानकारी मिल जाएगी तो डाटा अपलोड कर दिया जाएगा। हालांकि अब तक डेमो वर्जन भी नहीं देखने को मिला है। डेमो वर्जन तैयार होने के बाद फाइनल वेबसाइट कब तक तैयार हो पाएगी, यह कहना बेहद मुश्किल है।

प्राथमिकता के आधार पर...

उच्च शिक्षा विभाग में प्राथमिकता के आधार पर काम होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द उच्च शिक्षा की वेबसाइट तैयार कर सकें।

आर बी सुब्रमण्यम, अपर संचालक उच्च शिक्षा विभाग

क्यों होनी चाहिए वेबसाइट

किसी भी सरकारी महकमे की वेबसाइट दो कारणों से होनी जरूरी है। एक तो विभागीय कामकाज को सार्वजनिक सूचनाएं एक मुकम्मल जगह पर मिल सकती हैं। दूसरा उच्च शिक्षा की पेचीदगियां भी इसके जरिए समझी जा सकती हैं। एक तरह से वेबसाइट्स भी सिटीजन चार्टर का एक हिस्सा ही है।

सबसे बड़ी वजह

वेबसाइट होने की सबसे बड़ी वजह तो यह है कि राज्यभर में विभिन्न कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या करीब एक लाख तक है। इनमें से 80 फीसदी इंटरनेट यूजर हैं, जबकि शेष अप्रत्यक्ष रूप से नेट यूजर्स हैं।